शोध मंथन Vol. XVII No.2 July.-Sept. 2026 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X, Impact Factor 8.889 (SJIF)
https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i03.078

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के जीवन स्तर पर प्रभावः 21वीं सदी का अध्ययन

प्राप्तिः 10.08.2026
स्वीकृतः 12.09.2026

78

शिखा सिंह
शोधार्थिनी
डॉ राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी,
अयोध्या
ईमेलः *samsingh1008007@gmail.com*

सारांश

इक्कीसवीं सदी के प्रथम दो दषकों में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने महिलाओं के सशक्तिकरण और जीवन स्तर में सुधार के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ कीं। यह शोध आलेख इन योजनाओं के ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला, पोषण अभियान, वन स्टॉप सेंटर, महिला शक्ति केंद्र, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं सखी निवास जैसी योजनाओं ने महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वावलंबन एवं सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अध्ययन में पाया गया कि इन योजनाओं का ग्रामीण महिलाओं के जीवन में अधिक परिवर्तनकारी प्रभाव दिखाई दिया है, जबकि शहरी महिलाओं तक इनका विस्तार अपेक्षाकृत सीमित रहा है। योजनाओं के क्रियान्वयन में क्षेत्रीय असमानताएं, जागरूकता का अभाव एवं संस्थागत बाधाएं प्रमुख चुनौतियां रही हैं।

मुख्य शब्द

महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, जीवन स्तर, बाल विकास, लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्वावलंबन, मातृ स्वास्थ्य, कुपोषण, डिजिटल लिंग अंतराल, कौशल विकास, घरेलू हिंसा, वित्तीय समावेशन, निर्णय प्रक्रिया, सामुदायिक भागीदारी, नीति निर्माण, मूल्यांकन, सतत विकास लक्ष्य, अंतर–क्षेत्रीय असमानता

1. परिचय

इक्कीसवीं सदी ने भारत में महिलाओं के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन देखे हैं। इन परिवर्तनों में केन्द्रीय भूमिका निभाई है महिला एवं बाल विकास विभाग (Ministry of Women and Child Development) द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं ने। सन् 2006 में पष्थक मंत्रालय के रूप में

**This article has been peer-reviewed by the Review Committee of Shodhmanthan.*

स्थापित यह विभाग महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास के लिए नीति निर्माण एवं कार्यक्रम संचालन का दायित्व निभा रहा है। इस अध्ययन का उद्देश्य 21वीं सदी में इन योजनाओं के ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के जीवन स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों का बहुआयामी विश्लेषण प्रस्तुत करना है।

ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं की समस्याएं एवं आवश्यकताएं भिन्न हैं। ग्रामीण महिलाएं मूलभूत सुविधाओं के अभाव, सीमित शैक्षिक अवसरों, पारंपरिक सामाजिक ढांचे एवं आर्थिक निर्भरता जैसी चुनौतियों का सामना करती हैं। दूसरी ओर, शहरी महिलाएं यद्यपि शिक्षा एवं रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त करती हैं, किंतु वे भी सुरक्षा, आवास, प्रदूषण, यातायात एवं कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याओं से जूझती हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं ने इन विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों का सृजन किया है।

2. प्रमुख योजनाओं का परिचय एवं उद्देश्य

2.1 बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ (2015)

यह योजना लिंगानुपात में गिरावट एवं बालिका शिक्षा के प्रति उदासीनता को दूर करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत जन जागरूकता अभियान, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक एवं बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव को प्रोत्साहन दिया गया।

2.2 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (2017)

गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली यह योजना मातृत्व काल के दौरान महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती है।

2.3 उज्ज्वला योजना (2016)

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाली इस योजना ने महिलाओं को धुएं से मुक्त रसोई का अधिकार दिया।

2.4 पोषण अभियान (2018)

कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए प्रारंभ किए गए इस अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं, माताओं एवं किशोरियों के पोषण स्तर में सुधार लाने पर केंद्रीय ध्यान दिया गया।

2.5 वन स्टॉप सेंटर (2015)

हिंसा से प्रभावित महिलाओं को आश्रय, कानूनी सहायता, चिकित्सा सुविधा एवं परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित ये केंद्र संकटग्रस्त महिलाओं के लिए सहारा बने हैं।

2.6 महिला शक्ति केंद्र (2017)

ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ने, उनकी समस्याओं का समाधान एवं कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की गई।

2.7 सखी निवास (2016)

कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में कार्यरत एकल महिलाओं के लिए।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i03.078

3. ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर पर प्रभाव

3.1 शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन

बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत चलाए गए जागरूकता अभियानों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2014–15 से 2019–20 के बीच प्राथमिक स्तर पर बालिका नामांकन में 12: की वृद्धि हुई (शिक्षा मंत्रालय, 2020)। उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में यह प्रभाव अधिक स्पष्ट दिखाई दिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के माध्यम से बालिकाओं को आवासीय शिक्षा के अवसर उपलब्ध हुए हैं। इससे न सिर्फ बालिकाओं की शिक्षा में सुधार हुआ है, वरन उनके विवाह की उम्र में भी वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5 (2019–21) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 18 वर्ष से पूर्व विवाह करने वाली बालिकाओं के प्रतिशत में 7: की कमी आई है।

3.2 स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता ने उनके पोषण स्तर में सुधार किया है। आंकड़े बताते हैं कि इस योजना से जुड़ी महिलाओं में प्रसव पूर्व जांच कराने की दर में 22: की वृद्धि हुई (आईसीएमआर, 2021)। ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव की दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में जबरदस्त बदलाव लाया है। अब तक 8 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। इससे न केवल महिलाओं का समय बचा है, वरन उन्हें धुएं से होने वाली बीमारियों से भी राहत मिली है। ग्रामीण महिलाओं के सर्वेक्षण में 76: ने माना कि एलपीजी कनेक्शन मिलने के बाद उनकी आंखों एवं फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं में कमी आई है (पेट्रोलियम मंत्रालय, 2021)।

पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत किया गया। गर्भवती महिलाओं एवं किशोरियों को पोशाहार वितरण, आयरन की गोलियां एवं पोषण जागरूकता कार्यक्रमों से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य सूचकांकों में सुधार दर्ज किया गया है।

3.3 आर्थिक सशक्तिकरण में वृद्धि

महिला शक्ति केंद्र एवं अन्य कौशल विकास कार्यक्रमों ने ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समन्वय से स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाया गया। वर्ष 2022 तक 6.7 करोड़ ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ चुकी थीं, जिनमें से अधिकांश को महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं से सहायता प्राप्त हुई (नाबार्ड, 2022)।

इन समूहों के माध्यम से महिलाओं को बैंक ऋण, बाजार संपर्क एवं उद्यमिता प्रशिक्षण उपलब्ध हुआ। इसके फलस्वरूप ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि हुई एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भागीदारी भी बढ़ी। अध्ययन बताते हैं कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं में आत्मविश्वास एवं सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई है।

3.4 सामाजिक सुरक्षा एवं सशक्तिकरण

वन स्टॉप सेंटरों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक होने से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को त्वरित सहायता उपलब्ध हुई है। देश भर में संचालित 700+ वन स्टॉप सेंटरों में से 60: से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। इन केंद्रों ने अब तक 4 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की है (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2022)।

ग्रामीण महिलाओं के लिए यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले वे हिंसा की स्थिति में भी मौन सहन करने को मजबूर थीं। अब उनके पास शिकायत दर्ज कराने, कानूनी सहायता प्राप्त करने एवं आश्रय पाने का विकल्प उपलब्ध है।

4. शहरी महिलाओं के जीवन स्तर पर प्रभाव

4.1 शिक्षा एवं कौशल विकास में प्रगति

शहरी क्षेत्रों में पहले से ही बालिका शिक्षा की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बेहतर थी। यहां बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना का प्रभाव मुख्यतः उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने के रूप में दिखाई दिया। शहरी क्षेत्रों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित (STEM) विषयों में बालिकाओं का नामांकन बढ़ा है।

महिला शक्ति केंद्रों के माध्यम से षहरी महिलाओं को डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता एवं उद्यमिता विकास के कार्यक्रमों से जोड़ा गया। कोविड काल में डिजिटल माध्यम से चलाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने शहरी महिलाओं को घर बैठे कौशल विकास के अवसर प्रदान किए।

4.2 स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में प्रभाव

शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रभाव मुख्यतः अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं पर दिखाई दिया। यहां योजना की पहुंच सीमित रही क्योंकि शहरी क्षेत्रों की अधिकांश महिलाएं संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं एवं उन्हें मातृत्व लाभ अन्य स्रोतों से प्राप्त हो जाता है। फिर भी, शहरी झुग्गियों में रहने वाली महिलाओं तक इस योजना ने महत्वपूर्ण सहायता पहुंचाई है।

पोषण अभियान के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए कार्यक्रम चलाए गए। शहरी झुग्गियों में रहने वाली महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की दर में कमी लाने में इन प्रयासों को आंशिक सफलता मिली।

4.3 सुरक्षा एवं आवास के मुद्दे

सखी निवास योजना ने शहरी क्षेत्रों में कार्यरत एकल महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास का विकल्प प्रदान किया है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एवं चेन्नई जैसे महानगरों में इस योजना के तहत कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास एवं आवासीय परिसर स्थापित किए गए हैं।

वन स्टॉप सेंटर शहरी क्षेत्रों में भी सक्रिय हैं। शहरी महिलाओं के लिए ये केंद्र घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न एवं कार्यस्थल पर भेदभाव जैसी समस्याओं में सहायता प्रदान करते हैं। शहरी क्षेत्रों में इन केंद्रों की पहुंच अधिक है, किंतु जागरूकता के अभाव में कई महिलाएं इनका लाभ नहीं उठा पातीं।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i03.078

4.4 आर्थिक स्वावलंबन एवं नेतृत्व विकास

शहरी महिलाओं के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं उनके करियर निर्माण एवं नेतृत्व विकास में सहायक सिद्ध हुई हैं। महिला शक्ति केंद्रों के माध्यम से शहरी महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी, उद्यमिता विकास कार्यक्रम एवं नेटवर्किंग के अवसर उपलब्ध हुए हैं।

इन कार्यक्रमों का लाभ उठाने वाली शहरी महिलाओं में छोटे पैमाने पर स्वरोजगार शुरू करने, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पाद बेचने एवं सामुदायिक नेतृत्व की भूमिका निभाने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

5. ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं पर प्रभाव का तुलनात्मक विश्लेषण

5.1 समानताएं

- दोनों क्षेत्रों की महिलाओं में योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ी है
- दोनों क्षेत्रों में बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ है
- दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में सुधार हुआ है
- दोनों क्षेत्रों में महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय हुई हैं

5.2 अंतर

आयाम	ग्रामीण महिलाएं	शहरी महिलाएं
योजनाओं की पहुंच	आंगनवाड़ी एवं ग्राम स्तर पर सीमित संसाधन	शहरी केंद्रों में अधिक सुविधाएं किंतु पात्रता की सीमाएं
प्रभाव की गहराई	मूलभूत आवश्यकताओं में अधिक परिवर्तन	जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार किंतु आधारभूत समस्याओं का समाधान सीमित
भागीदारी का स्तर	सामुदायिक स्तर पर अधिक सक्रिय भागीदारी	व्यक्तिगत स्तर पर लाभ किंतु सामुदायिक भागीदारी सीमित
बाधाएं	सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाएं, भौगोलिक दूरी	संस्थागत बाधाएं, पात्रता की जटिलताएं

5.3 असमान प्रभाव के कारण

ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं पर योजनाओं का प्रभाव असमान रहने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

प्रथम, ग्रामीण महिलाएं विकास की निम्न आधार रेखा से शुरू करती हैं, अतः योजनाओं का उनके जीवन में परिवर्तनकारी प्रभाव अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। शहरी महिलाएं पहले से ही बेहतर स्थिति में होती हैं, अतः योजनाओं का प्रभाव सीमांत सुधार के रूप में दिखाई देता है।

द्वितीय, ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से हो पाता है। शहरी क्षेत्रों में योजनाओं की जानकारी एवं पहुंच का अभाव अधिक देखने को मिलता है।

तृतीय, ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के लिए पात्रता का दायरा व्यापक होता है जबकि शहरी क्षेत्रों में कई योजनाएं गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तक सीमित रह जाती हैं।

6. चुनौतियां एवं सीमाएं

6.1 क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियां

योजनाओं के क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियां सामने आई हैं। प्रशासनिक ढांचे की कमजोरियां, स्टाफ की कमी एवं अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण कई योजनाएं अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर अत्यधिक कार्यभार एवं अपर्याप्त पारिश्रमिक समस्या बना हुआ है।

6.2 जागरूकता का अभाव

योजनाओं के बारे में जागरूकता का अभाव सबसे बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5 के अनुसार केवल 55% ग्रामीण महिलाओं को ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जानकारी थी। शहरी क्षेत्रों में भी यह स्थिति बहुत बेहतर नहीं है।

6.3 भौगोलिक एवं सामाजिक असमानताएं

पूर्वोत्तर राज्यों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं की पहुंच अत्यंत सीमित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक महिलाओं तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में भी चुनौतियां हैं।

6.4 वित्तीय बाधाएं

योजनाओं के लिए आवंटित बजट का समय पर एवं पूर्ण उपयोग न होना एक बड़ी समस्या रही है। कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं में व्यवधान ने महिलाओं के स्वास्थ्य सूचकांकों को प्रभावित किया।

6.5 डिजिटल लैंगिक अंतराल

डिजिटल योजनाओं का लाभ उठाने में महिलाओं के सामने डिजिटल साक्षरता का अभाव बड़ी बाधा है। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 30% महिलाएं ही मोबाइल इंटरनेट का उपयोग कर पाती हैं, जबकि पुरुषों में यह दर 50% से अधिक है (निक्सी–आईएएमएआई, 2021)।

7. सफलता के उदाहरण एवं सीख

7.1 केरल का कुडुम्बश्री मॉडल

केरल में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को कुडुम्बश्री मिशन के साथ समन्वित किया गया। इससे ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को मजबूती मिली एवं वे विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम हुईं। केरल में महिला सशक्तिकरण के सूचकांक राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर हैं।

7.2 राजस्थान का आईसीडीएस मॉडल

राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण अभियान के तहत मजबूत किया गया। यहां पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की निगरानी की गई। इस मॉडल ने अन्य राज्यों के लिए भी मार्गदर्शन का कार्य किया।

7.3 महाराष्ट्र में वन स्टॉप सेंटर की सफलता

महाराष्ट्र में वन स्टॉप सेंटरों का नेटवर्क मजबूत किया गया। मुंबई एवं पुणे जैसे शहरी केंद्रों

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i03.078

से लेकर ग्रामीण जिलों तक इन केंद्रों ने हिंसा पीड़ित महिलाओं को प्रभावी सहायता प्रदान की है।

7.4 उज्ज्वला योजना का परिवर्तनकारी प्रभाव

मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में जबरदस्त बदलाव लाया है। यहां महिलाएं न केवल स्वच्छ ईंधन का उपयोग कर रही हैं, वरन इस बचे समय का उपयोग स्वरोजगार एवं बच्चों की देखभाल में कर रही हैं।

8. सुझाव एवं भावी दिशाएं

8.1 योजनाओं के समन्वय में सुधार

विभिन्न मंत्रालयों एवं योजनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता है। एक ही लाभार्थी को कई योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए एकीकृत डेटाबेस एवं सेवा वितरण प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

8.2 जागरूकता अभियानों को सशक्त बनाना

योजनाओं की जानकारी आम महिलाओं तक पहुंचाने के लिए सघन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। स्थानीय भाषाओं में, सरल भाषा में योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

8.3 डिजिटल समावेशन को बढ़ावा

महिलाओं की डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक डिजिटल केंद्र स्थापित किए जाएं जहां महिलाएं सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन कर सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें।

8.4 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सशक्तिकरण

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उचित पारिश्रमिक, प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। वे जमीनी स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उनके सशक्तिकरण से योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी होगा।

8.5 निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली को मजबूत बनाना

योजनाओं के नियमित मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र एजेंसियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। लाभार्थियों से नियमित फीडबैक लेने की व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।

8.6 लक्षित हस्तक्षेप

अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों एवं सबसे कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए विशेष लक्षित योजनाएं बनाई जानी चाहिए। अनुसूचित जनजाति एवं वनवासी महिलाओं, दिव्यांग महिलाओं, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम विकसित किए जाएं।

9. निष्कर्ष

21वीं सदी के प्रथम दो दशकों में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं ने भारतीय महिलाओं के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाए हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए ये योजनाएं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से लेकर आर्थिक स्वावलंबन तक का सफर तय करने में सहायक

सिद्ध हुई हैं। शहरी महिलाओं के लिए ये योजनाएं उनके अधिकारों, सुरक्षा एवं करियर निर्माण में सहायक रही हैं।

फिर भी, योजनाओं का प्रभाव क्षेत्रीय एवं सामाजिक असमानताओं से मुक्त नहीं है। जहां कुछ क्षेत्रों एवं वर्गों की महिलाओं ने इन योजनाओं का भरपूर लाभ उठाया है, वहीं अन्य अब भी इनसे वंचित हैं। डिजिटल विभाजन, जागरूकता का अभाव, क्रियान्वयन की कमजोरियां एवं सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाएं अब भी महिलाओं को इन योजनाओं का पूरा लाभ लेने से रोक रही हैं।

इन चुनौतियों के बावजूद, यह निर्विवाद है कि महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं ने भारतीय महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वावलंबन एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति में सहायक सिद्ध हुई हैं।

भविष्य की दिशा यह होनी चाहिए कि इन योजनाओं को और अधिक समावेशी एवं प्रभावी बनाया जाए। तकनीकी का अधिकतम उपयोग, जमीनी स्तर की संस्थाओं को सशक्त बनाना एवं सबसे कमजोर वर्गों की महिलाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना इस दिशा में प्राथमिकताएं होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक आवश्यकता नहीं, वरन राष्ट्र के सतत विकास के लिए अनिवार्य शर्त है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं महत्वपूर्ण माध्यम बनी रहेंगी।

सन्दर्भ

1. शर्मा, रमेश कुमार. भारत में महिला सशक्तिकरण की नीतियां एवं कार्यक्रम. राजकमल प्रकाशन, 2020, पृ0सं0–**145–178.**
2. सिंह, किरण. ''बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना का ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा पर प्रभाव'' शिक्षा एवं विकास शोध पत्रिका, खंड 12, अंक 3, 2021, पृ0सं0–**67–82.**
3. वर्मा, अंजली. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: एक मूल्यांकनात्मक अध्ययन. वाणी प्रकाशन, 2019, पृ0सं0–**112–135.**
4. गुप्ता, सुरेंद्र नाथ. ''उज्ज्वला योजना और ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव'' स्वास्थ्य एवं समाज, खंड 8, अंक 2, 2020, पृ0सं0–**33–48.**
5. जोशी, मीना. भारत में महिला सशक्तिकरण की चुनौतियां. ग्रंथ अकादमी, 2021, पृ0सं0–**201–225.**
6. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5 (2019–21). अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, 2021.
7. तिवारी, संजय. ''वन स्टॉप सेंटररू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए सहारा'' सामाजिक न्याय शोध पत्रिका, खंड 15, अंक 4, 2022, पृ0सं0–**91–106.**
8. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. वार्षिक रिपोर्ट 2021–22. भारत सरकार, 2022.
9. नाबार्ड. स्वयं सहायता समूहों का प्रभाव मूल्यांकन. नाबार्ड प्रकाशन, 2022.

10. पांडेय, शशि भूषण. ''ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के विकास का तुलनात्मक अध्ययन'' ग्रामीण विकास शोध पत्रिका, खंड 10, अंक 1, 2021, पृ0सं0–**45–60.**
11. आईसीएमआर. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का स्वास्थ्य पर प्रभाव: एक अध्ययन. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, 2021.
12. सक्सेना, प्रियंका. महिला सशक्तिकरण और सरकारी योजनाएं. हिंदुस्तान प्रकाशन, 2020, पृ0सं0–**78–96.**
13. शर्मा, अरविंद कुमार. ''महिला शक्ति केंद्र–उपलब्धियां एवं चुनौतियां'' लोक प्रशासन शोध पत्रिका, खंड 18, अंक 2, 2022, पृ0सं0–**112–128.**
14. निक्सी–आईएएमएआई. भारत में डिजिटल उपयोगकर्ता सर्वेक्षण. इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 2021.
15. वर्गीज, अल्फ्रेड. केरल में महिला सशक्तिकरण का मॉडल. केरल विश्वविद्यालय प्रकाशन, 2019, पृ0सं0–**156–172.**